भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नये आयाम : संभावनाएं तथा चुनौतियाँ

डॉ. भरत पारीक

सन् 1991 में नरसिंहराव सरकार के नेतृत्व में दिनांक 24 जुलाई, 1991 को नवीन उदारीकरण की नीति की घोषणा की गई थी तथा आर्थिक उदारीकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए गए थे। 1991 से लेकर अब तक उदारीकरण की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है तथा सरकार ने समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट सीमा को बढ़ाया है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जहां सन् 2000–2001 में 10,733 करोड़ रूपये था वही सन् 2011–12 में 1,65,146 करोड़ रूपये हो गया तथा वर्ष 2015–16 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत वृद्धि के साथ लगभग 2,62,322 करोड़ रूपये हो गया है। इसी क्रम में अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा में बदलाव किया गया है जिससे निश्चय ही दीर्घकाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा जो एक ओर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कारगर होगा तो दूसरी ओर इससे देश में उत्पादन तथा रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) हेतु नियमों में परिवर्तन की इस नीति के अनुसार रक्षा, उड्डयन तथा खाद्य पदार्थ क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश का रास्ता खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त फार्मा, सिंगल ब्रांड रिटेल, मोबाइल टीवी, केबल नेटवर्क, डीटीएच तथा पशुपालन क्षेत्र में भी विदेशी निवेश के नियमों में परिवर्तन करते हुए उनमें ढील दी गई है। इन परिवर्तनों के साथ ही अब भारतीय अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में विश्व की सबसे खुली अर्थव्यवस्था बन गयी है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है–

1. उड्डयन

वर्तमान में वायु परिवहन सेवा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की छूट है किन्तु नई नीति के अनुसार अब विदेशी कंपनियां भारतीय एयरलाइंस में 100 प्रतिशत निवेश कर सकेंगी। इसमें 49 प्रतिशत सरकार की बिना पूर्वानुमति (Automatic Route) से होगा। तथा इससे अधिक के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डो को अत्याधुनिक बनाने के लिए पहले से संचालित परियोजनाओं (Brown Field Projects) में भी 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

2 रक्षा

नई नीति के अनुसार रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश सरकार की पूर्वानुमति के बिना (Automatic Route) ही हो सकेगा तथा इससे अधिक के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

3	**खाद्य पदार्थ तथा ई–कॉमर्स**	फूड प्रोसेसिंग तथा ई–कॉमर्स क्षेत्र में सरकारी मंजूरी मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इस नीति के अनुसार विदेशी कंपनियों को देश में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना होगा तथा उन्हें देश में बेचने की अनुमति होगी।
4	**फार्मा**	अब तक फार्मा क्षेत्र में घरेलू कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत थी जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई नीति के अनुसार बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया है। तथा इससे अधिक के लिए सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है।
5	**सिंगल ब्रांड रिटेल**	नई नीति के अनुसार सिंगल ब्रांड रिटेल के नियमों में भी काफी ढील दी गई है। इसके अनुसार अब कंपनियां 3 साल तक आउटसोर्सिंग के नियमों में छूट ले सकती है। यदि वह भारत में नई कटिंग ऐज तकनीक का इस्तेमाल करती है तो उसे पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
6	**प्रसारण**	पूर्व में केबल, डीटीएच, मोबाइल टीवी, टेलीपोर्ट सेवा कंपनियों में 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की छूट प्रदान की गई थी जिसे अब परिवर्तित कर प्रसारण क्षेत्र में टेलीपोर्ट्स, डीटीएच, केबल नेटवर्क सेवा, मोबाइल टीवी आदि में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट दी गई है।

संभावनाएं तथा चुनौतियाँ –

विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में छूट सीमा बढाने से रोजगार अवसरों में वृद्धि, वित्तीय घाटे में कमी, कार्यकुशलता में वृद्धि, बचत एंव निवेश दर में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास, राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग, सर्वोत्तम तकनीकों का उपयोग जैसी अनेक संभावनाएं हो सकती है किन्तु इसके साथ ही विदेशी कंपनियों द्वारा शोषण, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, घरेलू उद्योगों के भविष्य पर संकट, बेरोजगारी की संभावना, विदेशी हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का भी भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दी गई ढील से उत्पन्न संभावनाएं एवं चुनौतियां निम्न प्रकार व्यक्त की जा सकती है–

1.	**उड्डयन**	भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में घरेलू यात्रियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक तेज गति से बढ़ रही है। घरेलू ट्रेफिक में एक साल में लगभग 22 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वर्तमान में देश में हवाई अड्डों की संख्या लगभग 476 हैं, जिनमें से कई हवाई अड्डे लगभग बंद पड़े हैं। 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट मिलने से बंद एयरपोर्ट पुनः शुरू होने की संभावना हैं। इसके अतिरिक्त देशी–विदेशी एयरलाइंस में प्रतिस्पर्धा होने से जहां एक ओर

यात्रियों को टिकिट सस्ते मिलने की उम्मीद है वहीं दूसरी ओर उन्हें सुविधाएं भी पहले की अपेक्षा बेहतर मिलने का अनुमान है। इससे ना केवल देशी एयरलाइंस को लाभ होगा अपितु विदेशी एयरलाइंस को भी एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। किन्तु चिंताजनक बात यह है कि देश की कुछ विमानन कंपनियों की माली हालत बहुत खराब है तथा वे लगातार घाटे में चल रही है। 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट मिलने से विदेशी निवेश होने की संभावना तो है किन्तु इसके लिए विमानन कंपनियों के पास बेहतर प्रबंधन तथा पर्याप्त संसाधन भी होने आवश्यक है।

2 रक्षा

रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट मिलने से रक्षा क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेंगी। ऐसी संभावना है कि इस क्षेत्र में विश्व की नामी कंपनियां निवेश करेंगी। किन्तु इस राह में समस्या यह है उन्हें इस अवस्था में भारत में रहकर हथियारों का उत्पादन करना होगा। संभव है अमरीका तथा चीन जैसे देश इस उत्पादन पर ऐतराज व्यक्त करे। इसके अलावा अमरीका जैसे राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध इसलिए अच्छे है क्योंकि भारत उनके हथियारों का बहुत बड़ा क्रेता है। अब यदि देश में ही हथियारों का उत्पादन होता है तो इसका सीधा दुष्प्रभाव हमारे आपसी संबंधों पर पड़ेगा फलस्वरूप हमारी विदेश नीति पर दूसरे देशों द्वारा दबाव बनाया जा सकता है।

3 खाद्य पदार्थ तथा ई–कॉमर्स

खाद्य पदार्थ तथा ई–कॉमर्स क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट मिलने से विदेशी कंपनियों की सक्रियता बढेगी तथा विदेशी निवेश के माध्यम से आने वाले उद्योगों पर देश में उत्पादित वस्तुओं को बेचने की अनिवार्य शर्त होने से घरेलू उत्पादकों को लाभ होगा एवं जिससे रोजगार के अवसर बढेंगे। किन्तु समस्या यह है इतने नियंत्रणों तथा शर्तों के चलते विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से कतरायेंगे।

4 फार्मा

हमारे देश में दवा उद्योग में लागू दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण विदेशी कंपनियां निवेश करने में हिचकिचाती थी। किन्तु अब सरकार ने इस क्षेत्र में बिना किसी पूर्वानुमति के 74 प्रतिशत तक निवेश की छूट प्रदान कर दी है। किन्तु इस क्षेत्र में 10 प्रमुख कंपनियां ही तेजी से आगे बढ़ रही है जिन्हें अपनी इक्विटी बेचने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे में 100 प्रतिशत की निवेश छूट मिलने के बावजूद कोई विदेशी निवेशक इन कंपनियों की इक्विटी भारी

कीमतों में खरीदने को राजी नहीं होगा। फलतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में छूट देने के उपरांत भी उसका फायदा मिलना संदिग्ध है।

5 सिंगल ब्रांड रिटेल

सिंगल ब्रांड रिटेल में तीन साल की छूट दी गई है तथा इसे पांच साल तक और बढ़ाया जा सकता है। इससे निश्चय ही एपल, डेल, सोनी जैसी कंपनियों को लाभ मिलेगा। किन्तु इन कम्पनियों में आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता अधिक होने से वे भारी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर सकती है। फलतः स्वदेशी कंपनियां तथा लघु तथा मध्यम उद्योग इनके सामने टिक नहीं पायेंगे। जिससे बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है।

6 प्रसारण

इसके परिणामस्वरूप देश में इनका व्यवसाय बढेगा जिससे रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। किन्तु चिंताजनक स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में छोटी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ेगा।

'व्याख्याता,
व्यावसायिक प्रशासन विभाग,
एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. (ऑटोनोमस) कॉलेज

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. Ahuja H.L. (2014). "*Economic Environment of Business*", S.Chand & Co., New Delhi.
2. Dutt Rudder and Sundaram K.P.M. (2015). "*Indian Economy*", S.Chand and Co., New Delhi
3. Kothari C.R (1997). "*Research Methodology*", Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 3rd edition.
4. Lamba A.J (2014). "*Retail in India*", Tata McGraw Hill, Second Print, Pg 60-120.
5. Pradhan Swapna (2009). "*Retailing Management: Text & Cases*", Tata McGraw Hill, 3rd edition.
6. Rangrajan C. (1998). "*Indian Economy*", U.B.S. Publishers, New Delhi.
7. Singh Dr. Man Mohan (1998). "*India's Economic Reforms and Development*", Oxford University Press, New Delhi.
8. Singh S.P. (2010). "*Economic Development and Planning*", S.Chand & Co., New Delhi.
9. The Financial Express- New Delhi
10. The Economic Times – New Delhi
11. The Hindustan Times – New Delhi
12. The Times of India – New Delhi
13. Rajasthan Patrika – Jaipur
14. Dainik Bhaskar – Jaipur